बिहार में व्यावसायिक शिक्षा

1266. श्री रणजीत सिंह :
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 अगस्त, 1991 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" के वोकेशनल एजुकेशन प्लान्स इन बिहार" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिहार में व्यावसायिक शिक्षा जुलाई, 1988 में प्रारम्भ की गई थी और केन्द्रीय सरकार ने इस शीर्ष के अन्तर्गत राज्य सरकार को एक निर्धारित धनराशि दी थी;

(ग) यदि हां, तो कितनी धनराशि दी गई थी और क्या यह भी सच है कि इस धनराशि का प्रयोग उन उद्देश्यों से अलग उद्देश्यों के लिए किया गया था जो धनराशि देते समय निर्धारित किए गए थे और परिणामस्वरूप व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली सुचारू रूप से नहीं चल सकी थी; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग "ग" का उत्तर "ना" में है, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से लाभान्वित हुए विद्यार्थियों के वर्षवार संख्या कितनी-कितनी हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार ने, 43 विद्यालयों में +2 स्तर के 129 व्यावसायिक अनुभाग शुरू करने के बिहार सरकार के प्रस्ताव को मार्च, 1988 में अनुमोदित किया था। दूसरे चरण में, 108 विद्यालयों में 324 व्यावसायिक अनुभाग शुरू करने के प्रस्ताव को मार्च, 1991 में अनुमोदित किया गया।

अब तक व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार ने 7.02 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की। बिहार सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार प्रदत्त निधियों का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया गया है।

(घ) व्यावसायिक शिक्षा प्रथम चरण में अनुमोदित 43 विद्यालयों में पहले ही शुरू की जा चुकी है। छात्रों का पहला बैच राज्य इन्टरमीडियट काऊंसिल द्वारा आयोजित सैद्धान्तिक और प्रयोगात्मक (प्रेक्टिकल) परीक्षा में क्रमशः जनवरी और मार्च, 1991 में बैठा था। कुल मिलाकर 922 छात्र परीक्षा में बैठे थे जिनमें से 816 सफल हुए।

Racket in supply of medicine

1267. SHRI P. K. JOGI:
KUMARI ALIA:
SHRI KRISHAN LAL SHARMA:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the Press Report which appeared in the 'Statesman' of the 15h July, 1991 regarding a racket in the supply of medicines by certain pharmaceutical suppliers to Civil and Defence Departments in connivance with some senior officers of the D.G.S.&D. and the Director General of Quality Assurance; and

(b) if so, what action has been taken by Government to find out the factual position and what are the results thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI SALMAN KHURSHEED): (a) Yes, Sir, in so far as publication of the news-report is concerned.

(b) The news reports relate to deregistration of a number of pharmaceutical firms as recommended by Director General of Quality Assurance (DG QA) who are responsible for capacity assessment of the firms supplying drugs against DGS&D contracts. The matter has been raised

with Ministry of Defence who are the Administrative Ministry of DG QA. The role of the DG QA in procurement of drugs and capacity verification is under examination by the Ministry of Defence.

Training-cum-Employment centres for Women

1268. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the number of training-cum-employment centres for women that have been established in different States;

(b) what are the details of such centres, State-wise; and

(c) what is the criteria of giving assistance for establishing such Centres for women by Voluntary Organizations?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS AND WOMEN & CHILD DEVELOOPMENT (MS. MAMTA BANERJEE): (a) 1933.

(b) A statement is enclosed.

(c) The applications for assistance under this scheme are sent by the eligible organisations through the State Governments/Union Territory Administrations. After a preliminary scrutiny they are considered by a Screening Committee chaired by the Secretary of the Department of Women and Child Development. The Screening Committee approves proposals which are viable, have marketing tie ups and provide sustained employment at reasonable levels.

Statement

NORAD projects sanctioned State-wise since 1982-83

S.No	States	No. of projects
1	2	3
1	Andhra Pradesh	40
2	Assam	1
3	Bihar	1
4	Gujarat	8
5	Haryana	20
6	Himachal Pradesh	7
7	Jammu & Kashmir	..
8	Karnataka	7
9	Kerala	7
10	Madhya Pradesh	3
11	Maharashtra	11
12	Manipur	2
13	Meghalaya	..
14	Nagaland	..